

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना शामिल

चर्चा में क्यों?

25 अक्टूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना-त्वरति सचिवाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बंदि

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2028 तक 2,584.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना को पूरा करने के लिये उत्तराखंड को 1,557.18 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है।
- इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में राम गंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह बांध मौजूदा गोला बैराज को अपनी 40.5 कमी. लंबी नहर प्रणाली और 244 कमी. लंबी नहर प्रणाली के माध्यम से पानी देगा, जो 1981 में पूरा हुआ था।
- इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल और ऊधम सहि नगर ज़िलों और उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली ज़िलों में 57,065 हेक्टेयर (उत्तराखंड में 9,458 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 47,607 हेक्टेयर) की अतिरिक्त सचिवाई की परिकल्पना की गई है।
- दो नई फीडर नहरों के निर्माण के अलावा, 207 कमी. मौजूदा नहरों का नवीनीकरण किया जाना है और परियोजना के तहत 278 कमी. पक्के फील्ड चैनल भी क्रयान्वति किये जाने हैं।
- इसके अलावा इस परियोजना में 14 मेगावाट के जल वदियुत उत्पादन के साथ-साथ हलद्वानी और आसपास के क्षेत्रों में 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पीने के पानी के प्रावधान की भी परिकल्पना की गई है, जिससे 10.65 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी।
- इस परियोजना के सचिवाई लाभों का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को भी होगा और दोनों राज्यों के बीच लागत/लाभ साझाकरण 2017 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुसार किया जाना है। हालांकि, पीने का पानी और बजिली लाभ पूरी तरह से उत्तराखंड के लिये ही परिकल्पित है।
- प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना (पीएमकेएसवाई)-
 - प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की पहुँच को बढ़ाना और सुनिश्चित सचिवाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का वसति करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि हैं।
 - भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में 2021-26 के दौरान पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को रुपए 93,068.56 करोड़ (37,454 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता) के समग्र परियोजना के साथ मंजूरी दी थी।
 - पीएमकेएसवाई का त्वरति सचिवाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक प्रमुख और मध्यम सचिवाई परियोजनाओं के माध्यम से सचिवाई क्षमता के निर्माण से संबंधित है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत अब तक 53 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं तथा 25.14 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सचिवाई क्षमता सृजित हुई है।
 - 2021-22 के बाद पीएमकेएसवाई के एआईबीपी घटक के अंतर्गत अब तक छह परियोजनाओं को शामिल किया गया था। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना एआईबीपी के अंतर्गत शामिल होने वाली सातवीं परियोजना है।



Inclusion of Jamrani Dam Multipurpose Project of Uttarakhand under PMKSY-AIBP*



- Estimated cost of Project is **Rs.2,584.10 cr**, including **Rs.1,557.18 cr** central assistance to Uttarakhand
- The project is scheduled to be completed in **March, 2028**

Benefits:-

- Additional irrigation of **57 thousand hectare** in Nainital & Udham Singh Nagar districts of Uttarakhand, Rampur & Bareilly districts in Uttar Pradesh
- Hydro power generation of about **63.4 Million Units** with installed capacity of **14 MW power plant**
- **42.70 million cubic metre (MCM)** of drinking water to Haldwani and nearby areas



Cabinet Decision
— 25 October 2023

*PMKSY-AIBP : Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana-Accelerated Irrigation Benefit Programme

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jamrani-dam-multipurpose-project-of-uttarakhand-included-under-pmksy-aibp>